(d) It is expected to add 1174.30 MW of new capacity in the Eastern Region during 1995-96. The tentative programme for the terminal year of the 8th Plan i.e. 1996-97 is for an addition of 973 MW capacity. Various other measures taken to improve the availability of power in the Eastern Region include expediting commissioning of new generating capacity, improving the performance of existing capacity, reduction in transmission and distribution losses, implementation of demand management and energy conservation measures etc.

Excise Collection

93. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have made any review of the performance of different States and also the Central Government on excise collection; and

(b) if so, the State-wise and Central Government's achievement thereon during the years 1994-95 and 1995-96?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M.V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a) and (b) Data regarding revenue collection from Union Excise duties is not maintained State-wise. Therefore, even though revenue receipts from Union Excises are monitored on a continuing basis, no review thereof on the basis of State-wise performance is made.

Figures of revenue collections from Union Excise duties, exclusive of cesses which are not administered by the revenue Department, are given below for 1994-95 and April 1995 to January 1996:

Year	Revenue (Rs. in crore)
1994-95 (P)	37466.55
1995-96 (P) (UptoJan '96)	32393.48

P-Provisiortal.

बिजली की दरों में वृद्धि

94. **श्रीमती सुषमा स्वराज** :

श्री राम जेठमलानी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 फरवरी, 1996 के दैनिक "टाइम्स आफॅ इंडिया" में "साल्वे स्ट्रेसिस नीड टू हाइक पावर टेरिफ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार देश में बिजली की दरों में वृद्धि करने को आवश्यक समझती है,

(ग) यदि हां,तो क्या यह भी सच है कि देश में कृषि क्षेत्र में दी जाने वाली बिजली की दर उसकी उत्पादन लागत से कम है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में कल कितनी प्रतिशत बिजली कृषि क्षेत्र में औसतन उपयोग हो रही है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला चिमनभाई पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। जनवरी, 1993 में आयोजित विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में अपनाई गई काग्र-योजना में, अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया था कि उत्पादन और आपूर्ति की बढ़ी हुई लागत को मद्देनजर रखते हुए सभी टैरिफों को आवधिक रूप से संशोधित किया जाना चाहिए।

(ग) जी, हां।

(घ) अखिल भारत आधार पर वर्ष 1993-94 में कृषि क्षेत्र को बेची गई विद्युत की प्रति यूनिट औसतन वसूली 17.847 पैसे/यूनिट थी, जबकि आपूर्ति की औसत लागत 154.75 पैसे/यूनिट थी। जनवरी, 1993 में आयोजित विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में पहले ही यह निर्णय ले लिया गया था कि कृषि टैरिफ को कम से कम 50 पैसे /कि.वा.आ. तक बढ़ा दिया जाना चाहिए । कुल बेची गई यूनिटों में से लगभग 30 प्रतिशत कृषि क्षेत्र को आपूर्ति की गई थी।

बिजलीघरों में संकट

95. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** :

श्री अनन्तराय जायसवाल :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: